

मुख्य समाचार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं— वैज्ञानिकों के योगदान को सराहा।
- मुख्यमंत्री ने कहा— प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना का विकास कर पर्यटकों की आमद में वृद्धि के लिए सरकार उठा रही कई कदम।
- हिमाचल में खाद्यानों की ई-निलामी करेगा एम.एस.टी.सी.— राज्य सरकार ने माईनिंग लीज के लिए समझौता ज्ञापन किया हस्ताक्षरित।
- राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने लंबित डी.ए. व एरियर के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा।

अंतरिक्ष दिवस

आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र को अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का भी दिन है।

इधर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के समर्पण और ईमानदार प्रयासों के फलस्वरूप चंद्रयान-3 मिशन सफल हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला जिला के शोधी में स्थापित विज्ञान अध्ययन व सृजनात्मकता केंद्र के माध्यम से बच्चों के लिए विज्ञान के अध्ययन को और अधिक रोचक व नवीन बनाया गया है। इस बीच राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आज एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थान के अध्येता प्रोफेसर जितेंद्र राय ने भारत के अंतरिक्ष मिशन का एक अवलोकन विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

पर्यटन

प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार चंडीगढ़-कुल्लू-धर्मशाला को जोड़ने वाले नए हवाई रूट का प्रस्ताव तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के दो प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है जिसके लिए संबंधित एयरलाइंस कंपनी और अन्य एजेंसियों के साथ चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें कुल्लू और धर्मशाला के बीच नई सीधी हवाई सेवा के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर पर्यटन अधोसंरचना का विकास कर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित कर रही है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिकी को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हवाई यात्रा सुविधा में वृद्धि करने के साथ-साथ राज्य सरकार नए हेलीपोर्ट भी विकसित कर रही है। प्रदेश की पर्यटन राजधानी जिला कांगड़ा के रक्कड़ व पालमपुर, चम्बा और किन्नौर जिला के रिकांगपियो में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 13 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

जगत नेगी

राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज रिकांगपिओ में सांगला व कामरू विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान साडा क्षेत्र की सीमा, ठोस-तरल कचरा प्रबंधन, जल निकासी, स्ट्रीट लाईट जैसी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जगत सिंह नेगी ने साडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने और अधोसंरचना विकास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री ने बैठक में उपस्थित गैर सरकारी सदस्यों से सीधा संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया। इससे पहले कल शाम जगत सिंह नेगी ने पूह खंड की मूरंग पंचायत में साढ़े 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित महिला मंडल भवन का लोकार्पण किया।

विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी ज़िले के कोटली उपमंडल के तहत कून-का-तर में ब्यास नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। दो सौ 80 फुट लम्बे सस्पेंशन वैली ब्रिज को रिकार्ड सात माह में निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पुल के बनने से मंडी सदर, धर्मपुर और जोगिन्द्रनगर क्षेत्र के लोगों को आवाजाही की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार ने मंडी वृत्त में सड़कों के निर्माण व रख-रखाव पर एक सौ 27 करोड़ 61 लाख रुपये की राशि खर्च की है।

इस बीच लोक निर्माण मंत्री ने 8 दिवसीय नलवाड़ मेला साईंगलू के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मंडी विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ से अधिक और नाबार्ड के तहत 23 करोड़ रुपये सड़कों पर खर्च किए जा रहे हैं।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश-विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन. ए. आई. आर. मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा।

हर्षवर्धन चौहान

राज्य सरकार ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के उपक्रम, मैटल स्क़्रैप, ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस समझौते के तहत प्रदेश में खनन पट्टे और कम्पोजिट लाईसेंस की ई-नीलामी सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सुन्नी तहसील और अर्की तहसील में दो चूना पत्थर खाद्यानों की नीलामी करेगी।

इस बीच उद्योग मंत्री ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता भी की। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल से मई के दौरान निगम ने लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है।

महासंघ

प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों के लंबित डीए और एरियर के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासंघ ने आज सचिवालय में फिर से जनरल हाउस का आयोजन किया और सरकार के खिलाफ नारे-बाजी की। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर फिजूलखर्ची का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है जबकि मंत्री, सीपीएस और विभागाध्यक्षों द्वारा मनमाने ढंग से फिजूलखर्ची की जा रही है। उन्होंने कहा कि माननीयों के लिए फिजूलखर्ची और अधिकारियों की नाकामी के चलते ही प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अगर सरकार 27 अगस्त तक उनकी मांगे नहीं मानती है तो कर्मचारी विधानसभा सत्र के दौरान काले बिले लगाकर विरोध प्रकट करेंगे।

इस बीच सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न विभागों में सितम्बर 2024 तक दो वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मियों को पहले की तरह साल में दो बार नियमित करने का सरकार से अनुरोध किया है।

नरेश चौहान

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की हितैषी है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाल की और एक लाख 36 हजार कर्मचारियों को उनका हक दिया है। नरेश चौहान ने कहा कि कर्मचारियों को अपनी मांग रखने का अधिकार है लेकिन सरकार के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप लगाकर आलोचना करना गलत है। उन्होंने कहा कि सचिवालय के कर्मचारी अन्यो के मुकाबले सरकार की आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझते हैं और कर्मचारियों द्वारा मांग रखने के लिए अपनाया गया रवैया अफसोसजनक है।

डे-बोर्डिंग स्कूल

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन की अमलैहड़ पंचायत में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए लगभग 2 दशमलव 8 हेक्टेयर भूमि को शिक्षा विभाग के नाम करने के लिए फॉरेस्ट कलियरेंस दे दी है। मंत्रालय ने इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाईन माध्यम से क्लियरेंस प्रदान कर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव वन को पत्र के माध्यम से सूचित किया है। वन वृत्त हमीरपुर के अरण्य पाल निशांत मंडोत्रा ने इसकी पुष्टि की है।

पूर्व विधायक

राज्यसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के आरोपों पर पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, देवेन्द्र भुट्टो और के.एल. ठाकुर आज बालूगंज थाने में पेश हुए। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है और मुख्यमंत्री से सरकार चल नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रबन्धन में मुख्यमंत्री विफल हो गए हैं। राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर फिजूलखर्ची करने और युवाओं की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया।

आयुक्त

राज्य कर व आबकारी आयुक्त डॉ. यूनस ने कहा है कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने और इसकी निगरानी करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब कारोबारियों द्वारा लाभांश की तय दरों से अधिक दाम वसूलने पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 व इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ओवर चार्जिंग में दोषी पाए जाने पर ठेकेदार को पहले उल्लंघन पर 15 हजार रुपये, दूसरे उल्लंघन पर 25 हजार रुपये, तीसरे उल्लंघन पर 50 हजार रुपये और चौथे उल्लंघन पर एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।